

संपादकीय

संयुक्त राष्ट्र से संबंध

संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था ने लगातार दूसरे वर्ष नएचआरसी-भारत की मान्यता को स्थगित कर दिया। इसके नीचे किंतु थी यह निर्णय अब मानवाधिकार परिषद और कुछ यूएनजीए कार्यकारों में मतदान करने की भारत की क्षमता को प्रभावित कर करता है। एनएचआरसी का मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और यह कॉलम इस बारे में है कि इसकी मान्यता क्यों स्थगित की ई थी। पिछले साल, 9 मार्च, 2023 को, गैर-सरकारी संगठनों (मेरे हित) के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकाय, ग्लोबल लायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को लिखा था। मने उससे भारत की मान्यता स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा योंकि एनएचआरसी की स्वतंत्रता, बहुलवाद, विविधता और जवाबदेही को कमी राष्ट्रीय संस्थानों पर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों (जिसे पेरिस सद्वितीय कहा जाता है) के विपरीत थी। हमारे पत्र और अन्य नागरिक माज प्रस्तुतियों का संज्ञान लेते हुए, वैश्विक निकाय ने भारत में ढंग से पूरा करने में विफलता पर विचार करने के बाद एनएचआरसी की पुनरु नाम्यता को 12 महीने के लिए टाल दिया। एनएचआरसी को अपनी प्रक्रियाओं और कार्यों में सुधार करने के लिए कहा गया था, लेकिन एक साल बाद भी ऐसा नहीं हुआ। यही गरण है कि मान्यता को दूसरी बार स्थगित करना पड़ा। तो, वे कौन वो चीजें थीं जो पेरिस सद्वितीय के विपरीत थीं? सबसे पहले स्वतंत्रता की कमी थी। एनएचआरसी के पदाधिकारियों की नियुक्ति और इसके कामकाज दोनों में। एनएचआरसी के अध्यक्ष और अन्य दस्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेताओं की एक समिति की सिफारिश के द्वारा पर की जाती है। राज्य सभा, और राज्य सभा के उपाध्यक्ष। लॉकिं, 2019 के बाद से, लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली रहा। यह गया है, जिससे चयन समिति में केवल एक ही विपक्षी आवाज ची है। सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद, चयन समिति में कमात्र विपक्षी आवाज की कड़ी असहमति के बावजूद, न्यायमूर्ति रुण मिश्रा को 31 मई, 2021 को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया था। दूसरी समस्या यह थी कि एनएचआरसी के पास पुलिस दिक्कारियों सहित राज्य द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी हैं। यह हितों का टकराव है, सरकारी स्तक्षेप से आजादी नहीं। 2023 की समीक्षा में यह बताए जाने के बावजूद, नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे ठीक करने या इसे शुरू करने के लिए परामर्श आमंत्रित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया शुरू नहीं हो। नवंबर 2023 में, सात पर्व आईपीएस अधिकारियों को एनएचआरसी

विशेष मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनमें से एक, जिस पर 2018 में भारत की संघीय जांच एजेंसी, सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में काम करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, को आतंकवाद, आतंकवाद विरोधी, सांप्रदायिक दंगों और हिंसा के विषयगत क्षेत्रों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। टेलिजंस ब्यूरो के एक पूर्व निदेशक को आयोग का सदस्य बनाया गया था। भारत को बार-बार एनएचआरसी में विविधता की कमी के बारे में चिंताओं के बारे में बताया गया है, और विविध भारतीय समाज प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके अपनी संरचना और कर्मचारियों बहुलवादी संतुलन रखने के लिए कहा गया है, जिसमें धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यक शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं। निःसंदेह इस देश में ऐसा नहीं किया गया, जहां प्रधानमंत्री अपने नावी भाषणों सहित लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी अपरते रहते हैं। फिर भी एक और मुद्दा भारत में नागरिक समाज और मनवाधिकार रक्षकों के साथ एनएचआरसी की प्रभावी भागीदारी की कमी थी। इस दिशा में, एनएचआरसी को भागीदारियों की प्रगतिशील रिखाषा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपने जनादेश की व्याख्या करने के लिए कहा गया था, और सभी मनवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने और राज्य अधिकारियों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। यह उन लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है जिन्होंने इस अमले को इस सरकार द्वारा तैयार किया है, जहां इसकी हिंसा का आरोप करने वाले सभी लोग छाष्ट-विरोधी हैं। हालाँकि, बाकी दुनिया से इस तरह नहीं देखती है, और उचित लोकतंत्रों को नागरिक समाज साथ जुड़ना चाहिए। भारत में, मनवाधिकार रक्षकों को यूरोपीय हित विभिन्न कठोर कानूनों के तहत बिना मुकदमे के वर्षों तक भारासत में रखा जाता है, लेकिन एनएचआरसी को कोई शिकायत नहीं आती है। इसमें भीमा कोरेगांव-एलार परिषद मामले के सिलसिले में जांच साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए लोग शामिल हैं यह इश्मीरी मनवाधिकार रक्षक खुर्रम परवेज, जो नवंबर 2021 से हिरासत हैं और उमर खालिद, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न विशेष प्रतिवेदकों द्वारा भारतीय अधिकारियों से इन व्यक्तियों को रिहा करने का आह्वान दिए गए थे। इन व्यक्तियों की स्थिति पर प्रतिक्रिया दिए गए समय पर हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं ठाया गया है। एनएचआरसी मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखण्ड सांप्रदायिक हिंसा और सुर्खियाँ बने अन्य मुद्दों पर बिल्कुल बेकार हो गए हैं। इसने खुद को महिमा में नहीं छिपाया है और यह और रक्कार अब जिस दुविधा में है, वह उनकी खुद की बनाई हुई है। अतर के पास वर्तमान में ऐसे रेटिंग हैं।

बाधाओं के बावजूद कई वजहों से भारत में ईवी का भविष्य बेहतर

संजय
पिछले कुछ वर्षों से अभी खरीदारी में बदलाव आया है। लोग पेट्रोल-डीजल वाहनों से बाजार से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे साल 15 लाख इलेक्ट्रिक भोक्ताओं की चाहत और उनकी वर्तन को लेकर नए उत्तराधिकारी भारत का खुदरा काम आया है। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ाव देने का उसे प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। उसे अपना रहा है। प्रवृत्ति उभरी कैसे और कैसे जार पकड़ रही है— यह लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों क्रांति पर गहराई ने नज़र लाई है। जरूरत है। इसके दो पहला, ग्लोबल वार्मिंग के विविध जागरूकता, जो वैश्विक भोक्ताओं को आकर्षित कर रही है।



का लाभ उठा रहा है। टाटा जैसी कार कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत को समझा है और इसे पूरा करने के लिए कम लागत वाली टियागो लॉन्च की है। वे ईवी के विभाग) को अलग कर दिया है। मैं पिछले महीने से किफायती ईवी की तलाश कर रही हूं। उनकी संख्या कम है। यदि आपके पास खर्च करने के लिए ज्यादा रुपये हैं, तो कई

भारी उम्मीदों के बीच मतदाता अनुमान लगाते रहते

विनाद
१४८



जा भा व्यक्ति था, उसका मतलब है कि उनका ध्यान हिंदू बहुसंख्यकों के पहचान करने में अटूट रहा है, जिससे वह और संघ परिवार हमेशा गलर्ट से, उत्साही हिंदुत्व प्रशंसक मानते

शामल हा गया था, षडकस्त भारत की दृष्टि को आजमाए हुए और परीक्षण किए गए फार्मूलेबद्ध विषेश अभियान के पक्ष में खारिज कर दिया गया था। कांग्रेस और क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों के खिलाफ, जो भारत को एक बहु-धार्मिक बहु-सांस्कृतिक सम्भवता के रूप में पुनर्संर्थापित करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं जो गरीब समर्थक है, हालांकि अमीर विरोधी नहीं है। जीवन-यापन के संकट को कम करने, बेरोजगारी से निपटने और विभाजनकारी बहुसंख्यकवाद द्वारा विकसित विकसित भारत के अस्पष्ट लक्ष्य को हराकर सामाजिक शिरता बहाल करने के कांग्रेस के दृष्टिकोण की रचनात्मक व्याख्याओं की बौछार की गई, जिसे भारतीय गुट के साझेदारों ने साझा किया था। भाजपा, मतदाता के पास उदास महसूस करने का हर कारण है। ऐसा ही लग रहा था जब चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए कि अप्रैल में पहले दो चरणों में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर जाने की जहमत उठाई थी। फिर मतदाता मतदान में संशोधन आया जिससे चुनाव में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रही। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक चुनावी दायर की गई कि संख्या में धीमी गति से कमी के साथ कुछ गड़बड़ है। यह देखते हुए कि लगभग 78 प्रतिशत भारतीय स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और मैसेजिंग ऐप सहित सोशल मीडिया के उत्साही उपभोक्ता हैं, यहां तक

कि आभियान सामग्रा में सबसे छाटा बदलाव भी तुरंत लाखों मतदाताओं को सूचित किया जाता है। 'पीपी डनामतरमम हालाँकि, दैनिक आए गार पर उपभोग की जाने वाली इतनी तेजी से बदलती जानकारी के बावजूद मतदाताओं की भूख अतृप्त प्रतीत होती है, जिससे ऐसी मांग पैदा होती है जिसे राजनेताओं को पूरा करना होगा। इस जरूरत को पूरा करने के लिए, यह पूरी तरह से अनुमान लगाया गया था कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को सख्ती से बढ़ावा देन के लिए वापस आ जाएगी, जो कि दूसरे पक्ष ने वास्तविकता में नहीं कहा था। महिलाओं के सोने के भंडार और पवित्र मंगलसूत्र पर स्पन, विरासत कर, अयोध्या में नव—पवित्र राम मंदिर पर तथाकथित घावरी तालाश लगाना, संरचना को बुलडोजर से गिराना, अनुसूचित जाति और जनजाति और ओवीसी से आरक्षण के लाभ में कटौती इन लाभों को मुसलमानों को हस्तांतरित करना, गोहत्या पर प्रतिवंध लगाना, यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की मुक्ति भी, अदिकाधिक उसी भावना का हिस्सा थी। श्री मोदी और उनके नफरत प्रचारकों की टीम ने पिछले 10 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मतदाताओं के लिए पूरी निष्पक्षता से कहें तो, यही संदेश वे भाजपा से तब से सुन रहे हैं जब से वह 1984 में अस्तित्व में आई और राम मंदिर अभियान शुरू हुआ। श्री मोदी और उनकी पार्टी ने जो शोर मचाया, वह विपक्ष को कुचलने के लिए प्रयाप्त हाना चाहा था, जिससे 2024 का लोकसभा चुनाव कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अजीब बात है कि ऐसा नहीं हुआ है। शुरुआत के लिए, कांग्रेस आलू गैस सिलेंडर और स्वास्थ्य देखभाल की कीमतों से निपटने के लिए भारत को वापस पटरी पर लाने के अपने घस्कल्प से विचलित नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि ब्रष्टाचार के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के कारण गिरफतारियों, कारावासों और कटुता से परेशान क्षेत्रीय और छोटी पार्टियां इस हद तक बची हुई हैं कि मोदी अभियान केंद्रीय विषय से भटकता जा रहा है क्योंकि उन्हें चुनौती से निपटने के लिए उपमार्गों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य के सत्तारूढ़ दलों का एक समूह भाजपा को इन राज्यों में अधिकतम सीटें जीतने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष एक नेतृत्वहीन इकाई होने के बजाय एक मूर्ख इकाई में बदल गया है। कौन सा पक्ष जीत रहा है और कौन सा पक्ष हार रहा है, इसके विश्वसनीय और अविश्वसनीय अनुमानों की बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके कि श्री मोदी कथा पर नियंत्रण बनाए रखने के अथक प्रचारक हैं। चूंकि जीत की उच्च उम्मीदें दोनों पक्षों को उत्साहित करती हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि कोई भी पक्ष हारने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी उम्मीदों की इस प्रतियोगिता में अज्ञात मात्रा रहस्यमय मतदाता की है, जिसकी प्राथमिकता और क्यों कोई नहीं जानता।

जैव विविधता पर मंडराता संकट चिंताजनक

जादृप
वर्लड व

पल्टु याइड के गर नेपर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते पांच दशकों में उत्तरी की 68 प्रतिशत जैव विविधता नष्ट हो गयी है। इस दौरान हर दस में से सात जैव प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा हानि मिठे पानी के प्रजातियों को हुई है, जिनकी जनसंख्या में 84 प्रतिशत की भारी कमी आयी है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि जैव विविधता के संरक्षण हेतु ईमानदारी से प्रयास किये गये, तो भी 2050 से पहले इसमें सुधार की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की भारत इकाई ने कहा है कि भारत में 12 प्रतिशत जंगली स्तनधारी जंतु और चिड़ियों की तीन प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, जबकि 19 प्रतिशत

चुनाव का मासम

ललित
चुनावी मौसम एक ऐसा समय होता है जब हर मुद्दा, चाहे वह कितना भी लंबे समय से दबा हुआ क्यों न हो, अचानक सार्वजनिक जांच के लिए सामने आ जाता है। मंच पर दाईं ओर प्रवेश करें, खोबरागड़े गाथा। जब आपने सोचा था कि यह एपिसोड चुपचाप समाप्त हो गया है, तो यह वापस आ गया है, अब देवयानी खोबरागड़े की कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में हाल ही में पदोन्नति के कारण पक्ष चान्दोपाय प्रत्यर्थी के साथ। यह पदोन्नति, जिसे भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के लोग जिनमें अनुभवी बाबू भी शामिल हैं योग्य नहीं मानते हैं, इसे गलत को सही करने के रूप में देख जाता है। उनके लिए 1999 बैं की आईएफएस अधिकारी सुश्रृंखोबरागड़े 2013 में एक राजनयिता नाटक की अनिच्छुक स्टार बन गा – जिसने भारत-अमेरिका संबंधों को बेहद निचले स्तर पर ला दिया अमेरिका में अपनी घरेलू नौकरान को कम वेतन देने के आरोप तक पर्याप्त उनकी गिरफ्तारी दर्द और

ता के लकड़ को बख्त हुए जा हम अपनी जीवनशैली को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मानवता उसी प्राकृतिक दुनिया को तेजी से नष्ट कर रही है, जिस पर उसकी समृद्धि और अस्तित्व टिका है। वनों, महासागरों, भूमि और वायु के दशकों से हो रहे दोहन और उन्हें जहरीला बनाये जाने के कारण हुए बदलावों ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, जानवरों और पौधों की 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गयी हैं। ये प्रजातियां बीते एक करोड़ वर्ष की तुलना में हजारों गुणा तेजी से विलुप्त हो रही हैं। जिस तेजी से ये प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उसे देखते हुए डायनोसोर के विलुप्त होने के बाद संख्या पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। रिपोर्ट में इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया था कि हम अर्थव्यवस्था, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य व जीवन की गुणवत्ता के मूल को ही नष्ट कर रहे हैं। अध्ययन में इस पर भी विचार-विमर्श किया गया था कि किस प्रकार हमारी प्रजातियों की बढ़ती पहुंच और भूख ने सम्यता को बनाये रखने वाले संसाधनों के प्राकृतिक नवीनीकरण को संकट में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के विशेषज्ञ जोसेफ सेटल के अनुसार, लघुकाल में मनुष्यों पर खतरा नहीं है, परंतु दीर्घकाल में यह कहना मुश्किल है। यदि ननुष्य विलुप्त होता है तो प्रवृत्ति अपना रास्ता खोज लेगी, क्योंकि वह हमेशा ऐसा कर लेती है। प्रकृति को बचाने के लिए बड़े बदलावों की जरूरत है। हमें हर सामग्री के उत्पादन, पैदावार और उसके उपभोग के तरीके में आमूलचूल बदलाव करना होगा।

दरअसल पशु-पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में ही अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं। प्राकृतिक आवास में ही इनकी जैविक क्रियाओं के बीच एक संतुलन बना रहता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दौर में विभिन्न कारणों से पक्षियों का प्राकृतिक आवास उजड़ता जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं। बाग-बगीचे उजाड़ कर इन जगहों पर खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। मोर जैसे पक्षी कीटनाशकों के चलते काल के गाल में समा रहे हैं।

साथ। यह पदोन्नति, जिसे भारतीय मीडिया में हंगामा मच गया। उसने पारंपरिक कंबोडियाई पौशक में एक से बेहतर कछ नहीं है। विदेश तिगुना भूगतान करना प

चुनावी मौसम एक ऐसा समय होता है जब हर मुद्दा, चाहे वह कितना भी लंबे समय से दबा हुआ क्यों न हो, अचानक सार्वजनिक जांच के लिए सामने आ जाता है। मंच पर दाईं ओर प्रवेश करें, खोबरागड़े गाथा। जब आपने सोचा था कि यह एपिसोड चुपचाप समाप्त हो गया है, तो यह वापस आ गया है, अब देवयानी खोबरागड़े की कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में हाल ही में पदोन्नति के कारण प्रक शान्तार्थ प्रत्यर्थी के

विदेश सेवा (आईएफएस) के लोग, जिनमें अनुभवी बाबू भी शामिल हैं, योग्य नहीं मानते हैं, इसे गलती को सही करने के रूप में देखा जाता है। उनके लिए 1999 बैच की आईएफएस अधिकारी सुश्री खोबरागड़े 2013 में एक राजनीयिक नाटक की अनिच्छुक स्टार बन गई – जिसने भारत–अमेरिका संबंधों को बेहद निचले स्तर पर ला दिया। अमेरिका में अपनी घरेलू नौकरानी को कम वेतन देने के आरोप के कारण उनकी मिशनारी दृढ़ और बेर्झमानी की, अमेरिकी अदालतों ने राजनीयिक छूट के कारण अंतत सहमति में सिर हिलाया, और भारत ने नौकरशाही बहादुरी का एक दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए उसे वापस धन भेज दिया, जिससे अमेरिकियों का राजनीयिक हैंगओवर का सामन करना पड़ा। भारत मानवाधिकारिकाय में खो सकता है वोट अब जब हम आम चुनाव के दौर में हैं सुश्री खोबरागड़े का नाम फिर रंग सामने आया है। इस बार, यह देश के न्याय साल के जन्म के लिए

शानदार फोटोशूट के सिलसिले में है, एक ऐसा दृश्य जिसने सोशल मीडिया को दिवाली की आतिशबाजी की तरह रोशन कर दिया। अनुभवी राजनयिक उनकी कंबोडियाई पोस्टिंग को उसी उत्साह के साथ ले रहे हैं, जिस तरह की आप एक कप गुनगुनी चाय के लिए उम्मीद करते हैं — इसे जीत से ज्यादा एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन किसी विवादास्पद अतीत से एक या दो भास्तर्णा ऐटा करने वाले आम चन्नाव मंत्रालय विदेश में संदिग्ध भूमि सौदों की जांच कर रहा है राजनयिक जगत से अन्य समाचारों में, विदेश मंत्रालय विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा कुछ संदिग्ध रियल एस्टेट सौदों की जांच में लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने इन मिशनों को, जो किराए की जगहों से संचालित हो रहे थे, जमीन खरीदने और दूतावास बनाने के लिए कहा था। इनमें से कुछ मिशन खरीदारी की होड़ में चले गए और जमीन के लिए बाजार मूल्य से दोगुना या सब छिपा रहता अगर इनमें से किसी एक देश की यात्रा के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक टीम ने लाल झंडा नहीं लहराया होता। सीएजी ने मानदंडों के घोर उल्लंघन का पता लगाया और पुष्टि की कि भुगतान की गई कीमतें बाजार दरों से कहीं अधिक थीं। अब जबकि इसे छुपाया नहीं जा सकता, विदेश मंत्रालय संदिग्ध भूमि सौदों की जांच करने के लिए मजबूर है। लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं है।

जारी रखने के लिए यह वाला जाग बुझाये जाना चाहिए। इस वाजार में बूलें तो यह वाला जाग बुझाये जाना चाहिए।

में ईवी का भविष्य बेहतर

तरह स्वचालित होने वाला है। भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक और हाईड्रिड वाहनों को अपनाने और विनिर्माण (फेम) ने ईवी अपनाने की प्रवृत्ति में इजाफा किया है। प्रोत्साहन आद्यारित सब्सिडी योजना ईवी अपनाने और उनके बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में परिवहन सुविधाओं को 30 फीसदी तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। यह वित्तीय प्रोत्साहन निर्माताओं और खरीदारों, दानों की मदद करता है। फेम के दूसरे चरण में सरकार का लक्ष्य देश भर में 2,700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। हालांकि, अब भी बहुत से भारतीय कार खरीदते वक्त इलेक्ट्रिक कार के प्रति संदेह में रहते हैं। सबसे बड़ी कमी बुनियादी ढांचे की है। हालांकि फेम इस अंतर को पाठने का वादा करता है। किंतु भारतीय

ऐसी वीजों में निवेश से हिचकते हैं, जो जल्दी उपलब्ध हो भी सकती है और नहीं भी। जब तक बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो जाता, पारंपरिक वाहनों की तुलना में ईवी को चुनने की संभावना कम है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के फलने-फूलने और बनाए रखने के लिए मजबूत सहयोगी तंत्र जरूरी है। यद्यपि कर छूट, प्रोत्साहन और पर्याप्त जागरूकता है, पर सबसे बड़ी बाधा उस आबादी को समझाना है, जो यथास्थिति बनाए रखने को प्राथमिकता देती है। जलवायु कार्रवाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है, फिर भी यह कहना मुश्किल है कि देश के लोग स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब बड़े पैमाने पर ई-वाहन विज्ञापनदाता भी मानते हैं कि कार चलाने वाली आबादी कुछ हद तक

जलवायु कार्यकर्ता हैं, यदि नहीं भी हैं, तो वे इस दिशा की ओर अग्रसर हैं। इसलिए उनके विज्ञापनों का असर काफी कम है, जहाँ समाज का नवप्रवर्तक व उत्साही वर्ग (समृद्ध लोग) ईवी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों से क्रांति नहीं आने वाली। जल्द ही जब ये नवप्रवर्तक गायब हो जाएंगे, तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे, जहाँ से चले थे। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतें भी ईवी को काफी हद तक बढ़ावा देने में मदद करती हैं। हालांकि बैटरी चार्जिंग मॉडल और ब्रांड पर भी निर्भर करता है, लेकिन किसी सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट पर कोई भी अपनी कार बैटरी को 400 रुपये से कम में पूरी तरह चार्ज कर सकता है, जबकि एक बार पेट्रोल की टंकी भरवाने की लागत बहुत ज्यादा होती है। मुख्य बाधा बैटरी चार्जिंग में लगने वाले समय की है।

छात्रा को करता था परेशान, पहले की मारपीट, फिर रेता गला

सहारनपुर, संवाददाता। बीपीईएस की छात्रा मानवी तोमर को आरोपी सागर लगातार परेशान कर रहा था। छात्रा ने परिजनों को इसके बारे में शिकायत की थी। परिजनों ने कई बार आरोपी को समझाया कि ऐसा न करें, लेकिन आरोपी अपनी हस्तकतों से बाज नहीं आया। पुलिस जांच में आया है कि आरोपी की पहले छात्रा के साथ कहासुनी हुई। उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद आरोपी ने धारादार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। मानवी हत्याकांड को जिस तरीके से दिनदहाड़े आबादी के बीच जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे गला रहा है कि आरोपी पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया था। जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी क्रैमर खानाले तो दिखाई दिया कि हत्याकांड से कुछ देर पहले आरोपी युक्त छात्रा के साथ गली में दिखाई दे रहा है। छात्रा को आमास नहीं था कि आरोपी की मरण क्या है। अन्यथा वह रात भी मारा सकती थी। मानवी हत्याकांड के बाद पुलिस पर भी सावल खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां पर वारदात हुई उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर सीओ कार्यालय है। जहां पर हर समय पुलिस रही है। इसके बावजूद आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया और आसानी से फरार भी हो गया।

मौसेरे भाई ने कराया केस दर्ज, हमारे सामने हुई हत्या

मूरका के मौसेरे भाई शिक्षक राहुल कुमार ने तहरीर में बताया कि वह मानवी को लेकर गंगोह आया था। उसे गंगोह बस स्टैंड से ई-रिक्शा में बैठकर किसी काम के लिए रुक गया था। तभी पिता मोहकम सिंह मानवी का आइडी कार्ड लेकर आए और नानौता चौराहे पर मिले। उसके बाद पिता और बेटा आइडी कार्ड देने के लिए मानवी के कॉलेज की तरफ चले। तभी रास्ते में रेस्टॉरेंट के पास वाले खाली प्लॉट में मानवी के साथ आरोपी सागर मारपीट कर रहा है। जब आवाज देकर उसे रोकना चाहा तो आरोपी ने हाथ में लिए धारादार हथियार से उनके सामने ही गला रेतकर मानवी की हत्या कर दी। उन्होंने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग निकला।

कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठे छात्र

मानवी की हत्यारे का जल्द से जल्द एनकार्टर करने की मांग करते हुए विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र कोतवाली में धरने पर बैठे गए। कुछ देर बाद वहां संजय कम्हेड़ा, पप्पू रादौर आदि के साथ पहुंचे सांसद प्रदीप चौधरी के पुत्र अंशुमन चौधरी ने कोतवाली प्रभारी से बात की। कोतवाली प्रभारी ने विद्यार्थियों को जल्द ही प्रभारी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया।

नकली चमड़ा उत्पाद बनाने वाली रेबीज से पीड़ित व्यक्ति की मौत

फैक्टरी में छापा मालिक गिरफ्तार

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में नामी कंपनियों के नकली सेलर उत्पाद बनाकर बेचने के आरोप में शहर की एक फैक्टरी के मालिक को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर दिया। कंपनी के अधिकारियों की सूचना पर अनवरगंज पुलिस ने माल बरामद कर कंपनी को सील कर दिया।

कॉपीराइट की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। इस पर पुलिस ने फैक्टरी पर छापारी संजिव हांडा और गोड़ा के फिरोजपुर निवासी शाजोहन व प्रसाद अपनी-अपनी कंपनियों के अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि कई दिनों से शहर में उनकी कंपनियों के नकली चमड़ा उत्पाद बनाकर बेचने की शिकायत मिल रही थी। इस पर बुधवार को अपरिहार्य की पुलिस ने उपचार की तरफ लगाए हैं।

हरियाणा के पंचकुला निवासी संजिव हांडा और गोड़ा के फिरोजपुर निवासी शाजोहन व प्रसाद अपनी-अपनी कंपनियों के अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि कई दिनों से शहर में उनकी कंपनियों के नकली चमड़ा उत्पाद बनाकर बेचने की शिकायत मिल रही थी। इस पर बुधवार को अपरिहार्य की पुलिस ने उपचार की तरफ लगाए हैं।

रेलवे फाटक पर 66 करोड़ से बनेगा पुल, एस्टीटेम दिल्ली भेजा

शामली, संवाददाता। शामली में बैंडर रेलवे फाटक पर उपरियाँ पुल के लिए उत्पादन अपनी सेतु निगम के अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम बनाकर भेजा है। जल्द ही पुल निर्माण की उमीद है।

पुल निर्माण के बाद शहर के लोगों को जाम से भी मुक्ति मिल सकेगी। मेरठ-करनाल हाईवे पर 89 नंबर रेलवे फाटक समेत देशमें के उपरियाँ पुलों और रेलवे स्टेशनों पर अधिकारियों को अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल के लिए भूमि की पैमाइश कर चुके हैं। शामली मिल ने उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों

लेन और अंडरपास में प्रयुक्त होने वाली भूमि खरीदने के लिए एस्टीटेम भाग रहा था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और शामली यानी मिल के अफसर 89 रेलवे फाटक उपरियाँ पुल की सर्विस लेने में प्रयुक्त होने वाली भूमि का 66 करोड़ रुपये का एस्टीटेम उत्पादक दो लोगों को जाम के लिए अधिकारियों की अंदर बनाकर बेचने के आरोप में अधिकारियों को शुरू होने से उन रोगियों